सौर ऊर्जा डेवलपरों की सरकार से गुहार, बजट में इसके उपकरणों पर मूल सीमा शुल्क लगाने से बचे

नई दिल्ली (ईएमएस)। देश के सौर ऊर्जा डेवलपरों ने सरकार से आगामी बजट में सौर ऊर्जा उपकरणों पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) लगाने से बचने की गुहार लगाई है। डेवलपरों का कहना है कि अभी कुछ समय के लिये सरकार को सौर ऊर्जा उपकरणों पर मूल सीमा शुल्क लगाने से बचना चाहिये। डेवलपरों को आशंका है कि यदि अभी शुल्क लगाया जाता है तो २०२२ तक १७५ गीगावॉट अक्षय ऊर्जा का सरकार का लक्ष्य पटरी से उतर सकता है। उद्योग जगत के अनुमान के अनुसार, देश में ३५ गीगावॉट नवीकरणीय (अक्षय) ऊर्जा क्षमता के लिये १.७५ लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है। लगभग ५० गीगावॉट स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाएं क्रियान्वयन में हैं। भारत ने पहले ही ९० गीगावॉट अक्षय ऊर्जा की क्षमता प्राप्त कर ली है, जिसमें ३७ गीगावॉट सौर और ३८ गीगावॉट पवन ऊर्जा शामिल है। भारत का २०२२ तक १७५ गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। इसमें १०० गीगावॉट सौर और ६० गीगावॉट पवन ऊर्जा शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। इससे पहले पिछले साल जून में बिजली मंत्री आर के सिंह ने सौर उपकरणों पर मूल सीमा शुल्क लगाने के सरकार के इरादे के बारे में स्पष्ट रूप से संकेत दिया था। सोलर पावर डेवलपर्स एसोसिएशन (एसपीडीए) के महानिदेशक शेखर दत्त ने कहा, 'घरेलू निर्माताओं के परिपक्व होने तक सौर उपकरणों पर बीसीडी को स्थगित करने की आवश्यकता है। कोविड-१९ महामारी के कारण

आत्मनिर्भर बिहार के लिए सात निश्चय-२ के लिए बजट में होगा प्रावधान

पटना ईएमएस)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आत्मनिर्भर बिहार के लिए सात निश्चय-२ की योजनाओं के लिए आम बजट में राशि का प्रावधान किया जाएगा। इसके संदर्भ में कई योजनाएं बनायी गई हैं, जिनका प्रावधान बजट सत्र में पेश होने वाले आम बजट में होगा। सात निश्चय-२ की योजनाओं पर वर्ष २०२१ में ही काम भी शुरू हो जाएगा। इसको लेकर योजनाओं से संबंधित सभी चीजों का सर्वेक्षण कराया गया है। जदयू मुख्यालय में आयोजित कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह के बाद पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट के बारे में पहले से कोई स्पेसिफिक बात नहीं बतायी जाती है। लेकिन, इतना कह सकता हूं कि बिहार के विकास को आगे बढ़ाने वाला बजट पेश होगा। बजट की सारी तैयारियां की जा रही हैं। विधानसभा एवं विधान परिषद का जो सत्र प्रारंभ होगा उसके संबंध में कैबिनेट का निर्णय हो चुका है। सारी चीजें नियत समय पर होंगी। स्वाभाविक है इस साल का सप्लिमेंट्री (अनुपूरक) बजट भी आएगा। इससे पूर्व जदयू द्वारा आयोजित कर्पूरी जयंती समारोह को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को ज़मीन पर उतारने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, लोकनायक जय प्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों से हमलोग प्रेरित होकर काम कर रहे हैं। हमलोगों ने न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर काम करते हुए हर इलाके और हर तबके का विकास किया है। हाशिए पर रह रहे लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विशेष पहल की गई। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को ५० प्रतिशत आरक्षण दिया गया, जिससे समाज के हर तबके की महिलाएं जनप्रतिनिधि के तौर पर जनसेवाओं से जुड़ीं। अतिपिछड़ों को अनुसूचित जाति, जनजाति की तरह ही उद्योग लगाने, शिक्षा प्राप्त करने एवं अन्य कई क्षेत्रों में सुविधाएं दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग सिर्फ सत्ता का सुख लेना चाहते हैं। हमारे लिए सत्ता का बस एक मतलब है और वो है सेवा। लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। मैं वचन देता हूं, जब तक हम हैं, लोगों की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी नीतियां बनायीं उसका लाभ सबको मिला है। सरकार में आने के पहले ही दिन से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समाज, अतिपिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि जननायक के साथ अन्याय क्यों हुआ? कर्पूरी ठाकुर जी ने अतिपिछड़ों को आरक्षण दिया।

सीबीएसई स्कूलों की संबद्धता प्रणाली में बदलाव करने में जुटा

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) स्कूलों की संबद्धता प्रणाली में बदलाव करने में जुटा है। इस प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ डेटा विश्लेषण पर आधारित किया जा रहा है। नई प्रणाली एक मार्च से प्रभावी होगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में निर्धारित प्रणालीगत सुधारों के लिए की गई विभिन्न सिफारिशों के अनुकूल इसमें बदलाव किया जा रहा। सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कहा, बोर्ड एनईपी में शिक्षा सुधारों को लेकर की गई सिफारिशों के अनुरूप संबद्धता प्रणाली और प्रक्रिया में बदलाव करने जुटा है।

हालांकि, सीबीएसई (से स्कूलों की) संबद्धता प्रणाली २००६ से ही ऑनलाइन है, पर संशोधित प्रणाली पूरी तरह से डिजिटल होगी और यह न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ डेटा विश्लेषण पर आधारित होगी। अनुराग त्रिपाठी ने कहा, ये बदलाव सीबीएसई संबद्धता प्रणाली के कार्य को सुगम बनाएगा, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के लक्ष्य के अनुरूप, स्वचालित होगा और इसमें डेटा के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे। इससे पारदर्शिता आएगी, समूची प्रणालीगत प्रक्रिया में कहीं अधिक जवाबदेही आएगी तथा सभी आवेदनों का शीघ्र एवं समयबद्ध निपटारा हो सकेगा। त्रिपाठी ने कहा कि बोर्ड जल्द ही नई प्रणाली पर एक विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा। बोर्ड ने नई प्रणाली के अनुसार आवेदन प्रक्रिया के लिए समय सीमा में भी संशोधन किया है। संशोधित समय सीमा के मुताबिक नई संबद्धता और संबद्धता को अपग्रेड करने के लिए हर साल तीन अवधि उपलब्ध की जाएगी। एक मार्च से ३१ मार्च, एक जून से ३० जून और एक सितंबर से ३० सितंबर। त्रिपाठी ने बताया कि संबद्धता विस्तारित करने के लिए आवेदन हर साल एक मार्च से ३१ मई तक स्वीकार किये जाएंगे। गौरतलब है कि देश भर में और विदेशों में सीबीएसई से संबद्धता प्राप्त २४,९३० स्कूल हैं, जिनमें दो करोड़ से अधिक छात्र और १० लाख से अधिक शिक्षक हैं। संबद्धता नियमावली १९९८

दिल्ली के बाद अब महाराष्ट्र में भी हल्ला बोल

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ यानी मुंबई के आजाद मैदान में एक रैली है। इस रैली में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों से हजारों की संख्या में किसान मुंबई पहुंच चुके हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि किसान रैली के मद्देनजर पुलिस ने दक्षिण मुंबई स्थित आजाद मैदान और उसके आसपास के इलाकों की सुरक्षा की विशेष तैयारी की है और राज्य रिजर्व पुलिस बल एसआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है, इसके साथ ही ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑल इंडिया किसान सभा एआईकेएस की महाराष्ट्र शाखा ने एक बयान जारी कर दावा किया कि नासिक से करीब १५ हजार किसान टैम्पो और अन्य वाहनों से मुंबई के लिए रवाना हुए हैं। बयान के मुताबिक सोमवार को होने वाली रैली को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) अध्यक्ष शरद पवार और महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के कुछ प्रमुख नेता संबोधित करेंगे। राज्य सरकार में सहयोगी कांग्रेस की राज्य इकाई पहले ही इस रैली का समर्थन कर चुकी है। कसारा घाट मार्च का नेतृत्व एआईकेएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक धावले और राज्य इकाई के प्रमुख किसन गुज्जर एवं महासचिव अजित नवाले ने किया। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र (सीटू) से जुड़े इगतपुरी और शाहपुर तहसील के फैक्टरी कामगारों ने इन किसानों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। कल्याण-भिवंडी क्रासिंग पर भी किसानों का स्वागत किया गया और खाने के पैकेट वितरित किए गए। किसान मुलुंद जांच चौकी के रास्ते मुंबई में दाखिल हुए। यह ठाणे की ओर से मुंबई में प्रवेश करने का रास्ता है। विक्रोली के कन्नमवार नगर में वाम दलों से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद किसान आजाद मैदान की ओर बढ़ गए जहां पर वे संयुक्त शेतकार कामगार मोर्चा (एसएसकेएम) के बैनर तले आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे जो गणतंत्र दिवस तक जारी रहेगा। बयान में कहा गया, ''यह रैली दिल्ली में कृषि कानूनों को वापस लेने,न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी और पूरे देश में फसलों की खरीद की मांग को लेकर दो महीने से प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में की जा रही है। इसके बाद प्रदर्शनकारी राजभवन की ओर मार्च करेंगे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को ज्ञापन सौपेंगे। बयान के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने २६ जनवरी के मौके पर आजाद मैदान में ही तिरंगा फहराने और किसानों और कामगारों के संघर्ष को सफल बनाने की शपथ लेने का फैसला किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि रैली के मद्देनजर इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि आजाद मैदान में एसआरपीएफ के जवानों की तैनाती के साथ ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि रैली स्थल पर १०० अधिकारियों और ५०० कांस्टेबल की अतिरिक्त तैनाती की गई है।

अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौके संबंधी अर्जी पर सुनवाई करेगा न्यायालय

नई दिल्ली (ईएमएस)। उच्चतम न्यायालय उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें उन अभ्यर्थियों को यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में बैठने का एक और अवसर दिये जाने का अनुरोध किया गया है जो पिछले साल कोविड-१९ महामारी की स्थिति के कारण अपने आखिरी मौके से वंचित रह गए। यह सुनवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले शुक्रवार को केंद्र ने इस बात पर जोर था कि वह सिविल सेवा के उन अभ्यर्थियों को एक और मौका देने के पक्ष में नहीं है जो २०२० में अपने आखिरी प्रयास के तहत परीक्षा नहीं दे पाये थे। न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर के नेतृत्व वाली पीठ ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू की २२ जनवरी को कही गई बातों को संज्ञान में लिया था और सरकार से इस आशय का हलफनामा दाखिल करने को कहा था। पीठ में न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुराई भी शामिल हैं। पीठ ने विधि अधिकारी से हलफनामे की प्रति सिविल सेवा अभ्यर्थी रचना के वकील को मुहैया कराने को कहा था, जिन्होंने परीक्षा में बैठने के लिए एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करने की याचिका के साथ अदालत का रुख किया है। इससे पहले, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया था कि सरकार उन सिविल सेवा अभ्यर्थियों को एक और अवसर प्रदान करने के मुद्दे पर विचार कर रही है जो यूपीएससी परीक्षा के अपने अंतिम प्रयास में शामिल नहीं हो पाए थे। शीर्ष अदालत ने पिछले साल ३० सितंबर को देश के कई हिस्सों में कोविड-१९ महामारी और बाढ़ के कारण यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने से इनकार कर दिया था, जो चार अक्टूबर को आयोजित की गई थी। हालांकि, उसने केंद्र सरकार और संघ लोक सेवा आयोग को यह निर्देश दिया था कि वे उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त मौका देने पर विचार करें, जिनका २०२० में आखिरी प्रयास है। पीठ को तब बताया गया था कि एक औपचारिक निर्णय केवल कार्मिक और प्रशिक्षण

चीन को भारत का फिर दो टूक जवाब

नई दिल्ली (ईएमएस)। सीमा विवाद पर जारी गतिरोध के बीच भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच करीब ढाई महीने के अंतराल के बाद रविवार को नौवें दौर की बैठक हुई। करीब १५ घंटे तक चली इस बैठक में भी भारत की तरफ से दो टूक कहा गया है कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर मई से पहले की स्थिति बहाल करे और पीछे हटे। एलएसी पर मई के बाद से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है। दोनों देशों के ५०-५० हजार सैनिक पूर्वी लद्दाख में तैनात हैं। सूत्रों के मुताबिक, नौवें दौर की बैठक में बातचीत का मुख्य उद्देश्य पिछली बैठक में बनी सहमतियों पर आगे बढ़ना था। यह तय किया जाना था कि दोनों देश किस प्रकार से अपने सैनिकों को टकराव वाले स्थानों से पीछे हटाएं। इसकी एक रुपरेखा पिछली बैठक में बनी थी, लेकिन अभी तक उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है। सेना से जुड़े सूत्रों ने बताया कि बातचीत चीन सीमा में पड़ने वाले मोल्डो में सुबह दस बजे शुरू हुई, जो देर रात तक चली। यानी कुल करीब १५ घंटे तक बातचीत हुई। इसमें भारत का नेतृत्व लेह स्थित १४वीं कोर के कमांडर लेफ्टेनेंट जनरल पीजीके मेनन ने किया, जबकि चीन की तरफ से तिब्बत क्षेत्र के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन शामिल हुए। पिछली बैठक छह नवंबर को हुई थी, जिसमें टकराव वाले स्थानों से सैनिकों को पीछे हटाने पर चर्चा हुई थी और इसका मोटा खाका भी तैयार किया गया था। इसके तहत पहले चरण में दोनों देशों के टैंक, तोप आदि हथियार हटाए जाने थे। दूसरे चरण में चीन को पेंगोंग त्सो के फिंगर-८ तक पीछे हटना था। वहीं, भारत को फिंगर-२ तक पीछे आना था। तीसरे चरण में पूरी तरह से मई से पहले की स्थिति बहाल करने पर बात हुई थी। हालांकि, आठवें दौर की बैठक में दोनों देशों ने संयुक्त बयान जारी कर उसे सकारात्मक बताया था, लेकिन इस प्रस्ताव पर प्रगति नहीं हुई। यही नहीं, नौवें दौर की बैठक में भी ढाई महीने का समय लग गया। रविवार को हुई बैठक में दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे।

केंद्र को कांग्रेस की चेतावनी किसानों की मांग पूरी नहीं हुई तो संसद सत्र होगा हंगामेदार

नई दिल्ली (ईएमएस)। कांग्रेस के लोकसभा में मुख्य सचेतक कोडिकुन्निल सुरेश ने कहा कि नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की किसानों की मांग यदि सरकार द्वारा नहीं मानी गई तो आगामी संसद सत्र हंगामेदार होगा। सुरेश ने कहा कि उनकी पार्टी किसानों के आंदोलन के मुद्दे को दोनों सदनों में जोरदार तरीके से उठाएगी। संसद का बजट सत्र २९ जनवरी से शुरू हो रहा है और यह दो हिस्सों में आयोजित होगा। पहला हिस्सा १५ फरवरी को समाप्त होगा और दूसरा हिस्सा आठ मार्च से आठ अप्रैल तक होगा। सुरेश ने कहा कि किसानों का आंदोलन, रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के कथित व्हाट्सऐप चैट जैसे मुद्दों को कांग्रेस द्वारा जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा, हमारी मुख्य प्राथमिकता किसानों का आंदोलन है और हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किसानों के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाने की योजना बना रहे हैं। हम इस मुद्दे पर चर्चा और बहस करने के लिए स्थगन प्रस्ताव जैसे सभी उपायों का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा, हम आगामी संसद सत्र के लिए एक संयुक्त रणनीति बनाने के लिए समान विचारधारा वाले दलों के साथ भी संपर्क में हैं और मुख्य मुद्दा किसान आंदोलन है। केरल से कांग्रेस के सांसद सुरेश ने कहा कि कांग्रेस किसानों की पीड़ा को समझती है जो ६० दिनों से अधिक समय से सड़कों पर हैं और उनमें से १४५ से अधिक अपनी जान गंवा चुके हैं, इसलिए इसे संसद के अंदर जोरदार तरीके से उठाया जाना चाहिए। सुरेश ने कहा, किसानों की मांग है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन सरकार इस पर सहमत नहीं हो रही है, इसलिए स्वाभाविक रूप से सत्र हंगामेदार होगा और हम सहयोग नहीं कर सकते हैं यदि किसानों की अनदेखी की जा रही है, हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते, हमें उनकी पीड़ा व्यक्त करनी होगी। सुरेश ने कहा कि यदि किसान सड़कों पर हैं, तो यह सदन में प्रतिबिंबित होगा क्योंकि किसान देश की रीढ़ हैं। हजारों प्रदर्शनकारी किसानों के प्रतिनिधियों के साथ सरकार की बातचीत में शुक्रवार को तब बाधा आ गई जब यूनियनों ने केंद्र द्वारा तीनों कानूनों को स्थगित करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कृषि मंत्री ने कठोर रुख के लिए बाहरी ताकतों को दोषी ठहराया। केंद्र द्वारा तीन कृषि कानूनों को कृषि क्षेत्र में बड़े सुधारों के रूप में पेश किया गया है, जो बिचौलियों को दूर करेगा और किसानों को देश में कहीं भी अपनी उपज बेचने की अनुमति देगा। हालांकि, प्रदर्शनकारी किसानों ने यह आशंका व्यक्त की

चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा कर रहे लेकिन मोदी सरकार चुप है: राहुल गांधी

नई दिल्ली (ईएमएस)। तमिलनाडु में अपने प्रचार के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाए कि चीन के सैनिकों ने भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है और ''५६ ईंचठ सीना रखने वाले व्यक्ति पड़ोसी देश का नाम तक नहीं ले सकते हैं। तमिलनाडु के तीन दिवसीय दौरे में यहां और पास के इरोड में सभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाए कि मोदी महज पांच या छह उद्यमियों के लिए देश का शासन चला रहे हैं। राज्य में अगले कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पश्चिमी जिलों में प्रचार अभियान पर निकले गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों, मजदूरों या सूक्ष्म, लघु या मध्यम श्रेणी के उद्यमियों के लिए नहीं है जो देश का भाग्य हैं। उन्होंने कहा, पहली बार भारत के लोग देख रहे हैं कि चीन की सेना भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा कर रही है। आज हम जब यहां बात कर रहे हैं उस समय हजारों चीनी सैनिक हमारे क्षेत्रों पर कब्जा कर रहे हैं और ५६ ईंच सीने वाला व्यक्ति चीन का नाम तक नहीं ले सकता है। यह हमारे देश की हकीकत है। लोगों से खुद को जोड़ने और भाजपा पर प्रहार करने के लिए 'तमिल भाषा और संस्कृति' का जिक्र करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि वह दिल्ली में तमिल लोगों का रखवाला बनना चाहते हैं और कहा कि वह भगवा दल को तमिल संस्कृति का अपमान नहीं करने देंगे। एक रोडशो के दौरान कुछ स्थानों पर लोगों को संबोधित करते हुए गांधी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह लोगों पर एक संस्कृति और एक भाषा थोप रही है और तमिलनाडु को 'दूसरे दर्जे' का स्थान बना रही है। अंग्रेजी में दिए गए भाषण में उन्होंने कहा, ''मैं तमिल भावना और संस्कृति को समझता हूं, स्वीकार करता हूं और उसका सम्मान करता हूं। मैं प्रधानमंत्री और भाजपा को तमिल लोगों का अपमान नहीं करने दूंगा। उनके भाषण का तमिल में अनुवाद किया गया।ठ उन्होंने कहा कि भारत विविध संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं का देश है। गांधी ने कहा, यह देश का संबल है। यह हमारा कर्तव्य है कि इस देश में हर भाषा, संस्कृति और धर्म की रक्षा करें। मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि तमिलनाडु का उनका दौरा लोगों को अपने 'मन की बात' कहने के लिए नहीं है या उन्हें सलाह देने या उन्हें क्या करना चाहिए, इस बारे में बताने के लिए नहीं है, बल्कि उनकी बात सुनने के लिए है, उनकी समस्याएं समझने और उनका समाधान करने के लिए है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के इतिहास और भाषा से शेष भारत काफी कुछ सीख सकता है।

एप डाउनलोड करना जरूरी नहीं, अपनी मर्जी है: दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली (ईएमएस)। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय में एक बार फिर सुनवाई हुई।दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर सुनवाई करते हुए सोमवार को कहा कि फोन में व्हाट्सएप डाउनलोड करना अनिवार्य नहीं है, ये स्वैच्छिक है। दिल्ली उच्च न्यायालय में व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि यह भी चिंता का विषय है कि भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए व्हाट्सएप द्वारा नीति में एकतरफा बदलाव किया गया।केंद्र सरकार ने कहा कि वॉट्सएप नई निजता नीति के संबंध में भारतीय उपयोगकर्ताओं और यूरोपीय उपयोगकर्ताओं के साथ अलग-अलग ढंग से पेश आ रहा है, जो चिंता का विषय है। इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कहा था कि अगर आपकी निजता प्रभावित हो रही है, तो आप व्हाट्सएप डिलीट कर दीजिए।दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि यह एक प्राइवेट एप है, अगर आपकी निजता प्रभावित हो रही है, तो आप व्हाट्सएप को डिलीट कर दीजिए। न्यायालय ने कहा कि क्या आप मैप या ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं? उसमें भी आपका डाटा शेयर किया जाता है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, ये निजता का उल्लंघन है। व्हाट्सएप जैसा प्राइवेट एप आम लोगों से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारियों को साझा करना चाहता है, जिस पर रोक लगाने की जरूरत है। इसपर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से कड़ी टिप्पणी की गई। व्हाट्सएप की प्राइवेसी नीति को लागू करने के खिलाफ एक वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई। याचिका में कहा गया कि ये संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार के खिलाफ है। इसलिए हम इस मामले में चाहते हैं कि कड़ा कानून बने। यूरोपीय देशों में इसको लेकर कड़े कानून हैं, इसलिए व्हाट्सएप की पॉलिसी वहां पर अलग है और भारत में कानून सख्त ना होने के कारण आम लोगों के डाटा को थर्ड पार्टी को शेयर करने पर ऐसे एप को कोई दिक्कत नहीं है।

ठबांग्लादेश और भारत एक हैं, अलग नहींठ

नई दिल्ली (ईएमएस)। गोवा में भारत के ५१वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हिन्दी और बांगला सिनेमा के दिग्गज अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और गायक बिस्वजीत चटर्जी को आज, २४ जनवरी, को गोवा में इंडियन पर्सनेल्टी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। अभिनेता कोयह पुरस्कार आज समापन समारोह में गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी, गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत और केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने एक साथ भेंट किया। पुरस्कार की घोषणा १६ जनवरी, २०२१ को महोत्सव के उद्घाटन समारोह में केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की थी। अभिनेता ने कहा: ''मैं इस पुरस्कार से सम्मानित करने के लिएभारत सरकार और सूचना और प्रसारण मंत्रालय को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। इस साल, हमें पता चला कि बांग्लादेश हमारा केन्द्र बिन्दु देश है, एक ऐसा देश जिसके साथ मेरा गहरा संबंध है। जब बांग्लादेश पर हमला हो रहा था, तब मुंबई में प्रतिभाशाली निर्देशक रित्विक गटक मेरे साथ थे और हम बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के भाषणों से प्रेरित होते थे। फिर ऋत्विक दा के सुझाव के अनुसार, हमने डॉक्यूमेंट्री देयर फ्लोज पद्मा, द मदर रिवरबनाई; मैंने बाद में ढाका जाकर इसे बंगबंधु को भेंट किया। मुझे उनके कार्यालय में दो चित्र मिले, जो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के थे। बांग्लादेश से मिले प्यार को मैं कभी नहीं भूल सकता। बांग्लादेश और भारत एक हैं, हम भाई-भाई हैं; हम अलग नहीं हैं। अभिनेता ने याद किया और गायक और निर्माता हेमंत कुमार के प्रति आभार व्यक्त किया, जो उन्हें बांग्लादेश से मुंबई ले आए।

सिक्किम के नाकू ला में भारतीय जवानों ने चीन की घुसपैठ को किया नाकाम, २० चीनी सैनिक घायल

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारत और चीन के बीच पिछले साल मई की शुरुआत से सीमा पर गतिरोध जारी है। एक बार फिर से भारत और चीन के जवानों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर झड़प की खबर सामने आई है। यह झड़प तीन दिन पहले सिक्किम के नाकू ला में हुई जब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के सैनिकों ने यथास्थिति को बदलने की कोशिश की थी। उसके कुछ सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में बढ़ने की कोशिश की। सीमा पर तैनात भारतीय सेना के चौकस जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें रोक दिया। इस झड़प में चीन के २० सैनिकों के घायल होने का समाचार है। वहीं भारत के ४ सैनिक भी इस झड़प में बहादुरी से लड़ते हुए घायल हुए हैं।अब इसे लेकर भारतीय सेना ने बयान जारी किया है। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर भारतीय सेना ने कहा कि 'यह स्पष्ट किया जाता है कि २० जनवरी को सिक्किम के नाकू ला में भारतीय सेना और चीन के पीएलए सैनिकों के बीच मामूली झड़प हुई थी। इसे स्थानीय कमांडरों द्वारा स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार हल कर लिया गया था। तीन दिन पहले नाकू ला में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हो गई। इसमें भारतीय सेना के चार जवान जबकि चीन के २० सैनिक घायल हो गए हैं।

भारतीय जवानों ने न केवल चीन के मंसूबों पर पानी फेरा बल्कि पीएलए के सैनिकों को भी खदेड़ दिया। फिलहाल सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण लेकिन स्थिर है। भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारतीय क्षेत्र के साथ सभी प्वॉइंट पर मौसम की स्थिति खराब होने के बावजूद कड़ी चौकसी बरती जा रही है।

सीमा पर जारी तनाव को कम करने के लिए रविवार को मोल्डो में भारत और चीन ने नौवे दौर की कॉर्प्स कमांडर स्तर की वार्ता की जो देर रात ढाई बजे तक चली। १५ घंटे तक चली इस वार्ता में सीमा पर तनाव कम करने को लेकर बातचीत हुई। वार्ता के दौरान भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि टकराव वाले क्षेत्रों में डिसइंगेजमेंट और डी-एस्केलेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चीन के ऊपर है। सिक्किम के नाकू ला में चीनी सेना द्वारा घुसपैठ की कोशिश उस समय के लिए मुस्तैद हैं।

कश्मीर में शीत लहर का प्रकोप बढ़ा!

श्रीनगर (ईएमएस)। कश्मीर घाटी में सप्ताहांत में बर्फबारी के बाद ज्यादातर इलाकों में शीत लहर का प्रकोप बढ़ गया है और न्यूनतम तापमान में कई डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से ५.२ डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया। वहीं काजीगुंड में न्यूनतम तापमान शून्य से ५.५ डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान शून्य से ११.५ डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। वहीं पहलगाम में न्यूनतम तापमान शून्य से ११.९ डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। कुपवाड़ा में न्यूनतम तापमान शून्य से ३.१ डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। कोकरनाग में तापमान शून्य से ८.४ डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। अभी चिल्लई-कलां की चपेट में है। यह ४० दिन की अवधि है, जिसमें कड़ाके की सर्दी पड़ती है और घाटी शीत लहर की चपेट में होती है तथा तापमान शून्य से कई डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। ऐसी स्थिति में यहां के जलाशयों और पाइपलाइन में पानी जमने लगता है। वहीं इस अवधि में बर्फबारी की संभावना खास तौर पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक होती है। चिल्लई कलां ३१ जनवरी को समाप्त होगा।